हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

श्री कान्त शेकारी

13 सितंबर, 2004

[न्यायाधिपति अरिजीत पासायत और न्यायाधिपति प्रकाश प्रभाकर नौलेकर]

दंड संहिता, 1860-धारा 376 और 506-शिक्षक द्वारा छात्रा से बलात्कार, पीड़िता गर्भवती हो गई - उसके साक्ष्यों पर भरोसा करते हुए, विचारण न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया - लेकिन उच्च न्यायालय ने उसे बरी कर दिया - बरी किए जाने के खिलाफ अपील - अपील पर, माना गया: पीड़िता की सहमति का प्रश्न अप्रासंगिक था क्योंकि दस्तावेजी साक्ष्य ने आज यह साबित कर दिया घटना की और यहां तक कि जब एफआईआर दर्ज की गई, तब भी पीड़िता की उम्र लगभग 14 साल थी - उच्च न्यायालय ने यह दिखाने के लिए पीड़िता पर बोझ डालकर गलती की कि कोई सहमति नहीं थी - बचाव पक्ष में आरोपी द्वारा सहमति की याचिका नहीं ली गई थी - हाई कोर्ट ने भी गलती की पीड़िता, एक नासमझ लड़की और उसकी अनपढ़ मां की गवाही पर संदेह करने की तारीखों के बारे में काल्पनिक गणना - एफआईआर दर्ज करने में देरी को संतोषजनक ढंग से समझाया गया - गलत निहितार्थ स्वीकार्य होने के लिए बहुत उथला है - उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया गया - विचारण न्यायालय के आदेश को बहाल किया गया।

दंड संहिता, 1860-धारा 228ए, 376, 376-ए, 376-बी, 376-सी और 376–डी यौन अपराध-पीड़ित की पहचान प्रकट करने के लिए सजा-उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के फैसले के मुद्रण या प्रकाशन से संबंधित प्रतिबंध नहीं-आयोजित, ऐसे पीड़ित के सामाजिक उत्पीड़न या बहिष्कार को रोकें जिसके लिए धारा 228-ए

अधिनियमित किया गया था, यह उचित होगा कि न्यायालय के निर्णयों में पीड़ित का नाम इंगित न किया जाए।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 21-जीवन का अधिकार-महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध, एक महिला की निजता और पवित्रता के अधिकार पर एक गैरकानूनी घुसपैठ है-न्यायालयों से ऐसे मामलों को अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ निपटने की अपेक्षा की जाती है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रतिवादी-अभियुक्त ने अपने कक्षा 4 के छात्रा विदिम को एक प्रश्न हल करने के लिए स्कूल के घंटों के बाद इंतजार करने के लिए कहा, जबकि उसने अन्य छात्रों को जाने की अनुमति दी। पीड़िता क्लास में ही रह गई कमरे में जब प्रतिवादी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए। चूंकि उसने पीड़िता को धमकी दी थी इसलिए उसने यह बात किसी को नहीं बताई। कुछ दिनों बाद प्रतिवादी ने पीड़िता के साथ दोबारा यौन संबंध बनाए। वह गर्भवती हो गई और बाद में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर प्रतिवादी को आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत दंडनीय अपराधों के कथित कमीशन के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ा। पीड़िता के सबूतों पर भरोसा करते हुए, ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी को दोषी ठहराया और 7 साल की कैद की सजा सुनाई। जुर्माना भी लगाया गया। इसके अलावा, प्रतिवादी को पीड़िता को 10,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और प्रतिवादी को इस आधार पर बरी करने का निर्देश दिया कि पीड़िता की उम्र 16 वर्ष से अधिक थी; अभियोजन पक्ष द्वारा यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं रखा गया कि पीड़िता ने इस कृत्य के लिए सहमति नहीं दी थी; और यह कि पीड़िता और उसकी मां द्वारा कथित बलात्कार का जो समय बताया गया था, वह चिकित्सीय साक्ष्यों द्वारा असंभव है।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलकर्ता-राज्य ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय उचित परिप्रेक्ष्य में तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति का विश्लेषण करने में विफल रहा और प्रासंगिक मामलों को विचार से बाहर रखा और अभिमानी निष्कर्ष निकाले और इसलिए, निर्णय को रद्द किया जाना चाहिए। .

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1.1. पूर्व पीडब्लू6/ए से पूर्व पीडब्लू6/सी यानी पीड़िता के स्कूल में प्रवेश और उसके अध्ययन की अवधि से संबंधित रिकॉर्ड यह साबित करते हैं कि आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार पीड़िता की जन्म तिथि 10.4.1979 थी। इसलिए, घटना की तारीख पर और यहां तक कि जब 20.11.1993 को एफआईआर दर्ज की गई थी तब भी वह लगभग 14 वर्ष की थी, और इसलिए पीड़िता की सहमति का सवाल वास्तव में कोई मायने नहीं रखता था। [387 बी-सी)

1.2. अन्यथा भी ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गंभीर गलती कर गया है कि पीड़िता ने यह नहीं दिखाया है कि यह कार्य उसकी सहमति से नहीं किया गया था। यह दिखाना पीड़िता का काम नहीं था कि कोई सहमति नहीं थी। तथ्यात्मक रूप से भी निष्कर्ष शुरू से ही गलत है, यानी उस चरण से जब एफआईआर दर्ज की गई थी और उसके साक्ष्य में एक स्पष्ट बयान था कि पीड़िता के विरोध के बावजूद बलात्कार जबरन किया गया था। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा यह दिखाने के लिए पीड़ित पर बोझ डालना गलत था कि कोई सहमति नहीं थी। सहमति का प्रश्न वास्तव में अभियुक्त द्वारा बचाव का मामला है और यह दिखाने के लिए सामग्री रखना उसका काम था कि सहमति थी। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिरह के दौरान और सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए बयान में सहमति की दलील नहीं दी गई या दलील नहीं दी गई। वास्तव में सीआरपीसी

की धारा 313 के तहत बयान में दलील पूरी तरह से इनकार और गलत आरोप थी। [387-डी-ई]

1.3. हाईकोर्ट ने पीड़िता और उसकी मां की गवाही पर संदेह करने के लिए तारीखों के संबंध में काल्पनिक गणना करने में भी गलती की है। गवाहों ने जो कहा था वह अनुमानित तारीखें या अवधियाँ थीं, न कि यह कि उन्हें सटीकता के साथ गिना जाना था। जैसा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से पता चलता है, पीड़िता कोई बुद्धिमान लड़की नहीं है। वह तीसरे प्रयास में कक्षा 3 पास कर गई। उसकी माँ, एक देहाती महिला, व्यावहारिक रूप से अनपढ़ है। उनके साक्ष्यों की सूक्ष्म दृष्टि से जांच करना न्यायोन्मुख न्याय व्यवस्था का अपमान होगा। (387-एफ-जी]

1.4. उच्च न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने में तथाकथित देरी के लिए अभियोजन पक्ष की बात पर भी अविश्वास किया है। लेकिन अभियोजन पक्ष ने ऐसा नहीं किया न केवल कारणों की व्याख्या की बल्कि इस बात को साबित करने के लिए ठोस सबूत भी दिए कि देरी क्यों हुई। जैसा कि तथ्यात्मक परिदृश्य से पता चलता है, पीड़िता अपने साथ हुई विपत्ति से पूरी तरह अनजान थी। ऐसा होने पर, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में मात्र देरी किसी भी तरह से अभियोजन संस्करण को कमजोर नहीं बनाती है। किसी भी स्थिति में, जब बलात्कार के आरोप शामिल होते हैं तो देरी स्वयं आरोपी के लिए कोई राहत देने वाली परिस्थिति नहीं होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी को अभियोजन मामले को खारिज करने और इसकी प्रामाणिकता पर संदेह करने के अनुष्ठानिक फार्मूले के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यह अदालत को केवल यह देखने और विचार करने के लिए तैयार करता है कि क्या देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण पेश किया गया है। एक बार जब यह पेश किया जाता है, तो न्यायालय को केवल यह देखना होता है कि यह संतोषजनक है या नहीं। ट्रायल कोर्ट ने वास्तव में स्थिति का विस्तार से विश्लेषण किया और सही निष्कर्ष पर पहुंचा कि

एफआईआर दर्ज करने में देरी के कारणों को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। (387-एच; 388-ए-बी]

तुलसीदास कनोलकर बनाम गोवा राज्य, (2003] 8 एससीसी 590, पर भरोसा किया गया।

2. कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है कि बलात्कार की शिकार महिला की गवाही को भौतिक विवरण की पुष्टि के बिना क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। वह एक घायल गवाह की तुलना में ऊंचे स्थान पर है। हालांकि, यदि अदालत तथ्यों पर अभियोक्ता के संस्करण को उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार करना मुश्किल लगता है, वह प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य की खोज कर सकता है, जो उसकी गवाही को आश्वासन देगा। आश्वासन, पुष्टि की कमी, जैसा कि एक साथी के संदर्भ में समझा गया है, पर्याप्त होगा। [388-जी-एच; 389-ए]

3. अभियुक्त का यह कथन कि उसे झूठा फंसाया गया क्योंकि पीड़िता का भाई परीक्षा में सफल नहीं हुआ था और इसलिए, उसके परिवार को अभियुक्त के प्रति द्वेष था, यह स्वीकार करने योग्य नहीं है। घटना जिसमें अभियुक्त और माँ और भाई शामिल थे पीड़िता की घटना करीब एक दशक पहले हुई थी. इस बात की दूर-दूर तक संभावना नहीं है कि यह गलत निहितार्थ का आधार होगा। किसी भी हालत में कोई भी कम उम्र की लड़की और उसके माता-पिता किसी व्यक्ति पर जबरन यौन संबंध बनाने का झूठा आरोप लगाकर उसके पूरे भविष्य को खतरे में नहीं डालना चाहेंगे। [389-बी-सी]

4. जिस यौन अपराध के लिए धारा 228 लागू की गई है, उसके पीड़ित के सामाजिक उत्पीड़न या बहिष्कार को रोकने के सामाजिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, यह उचित होगा कि निर्णयों में, चाहे वह इस न्यायालय का हो, उच्च न्यायालय

का हो या निचले न्यायालय का हो। , पीड़ित का नाम इंगित नहीं किया जाना चाहिए। [385-बी-सी)

कर्नाटक राज्य बनाम पुट्टराजा, (2003) 8 सुप्रीम 364, पर भरोसा किया गया।

5. यौन हिंसा एक अमानवीय कृत्य होने के अलावा एक महिला की निजता और पवित्रता के अधिकार पर एक गैरकानूनी घुसपैठ है। यह बुनियादी मानवाधिकारों के खिलाफ एक अपराध है, और पीड़ित के सबसे प्रिय मौलिक अधिकारों, अर्थात् भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के अधिकार का भी उल्लंघन है। न्यायालय से इसलिए, महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध के मामलों से अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटने की अपेक्षा की जाती है। (384-ई-जी)

मदन गोपाल कक्कड़ बनाम नारायण दुबे और अन्य, (1992) 2 अपराध 168 और श्री बोधिसत्व गौतम बनाम मिस सुभ्रा चक्रवर्ती, एआईआर (1996)एससी 922, संदर्भित

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 589/1999

1996 के आपराधिक अपील संख्या 278 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 10.11.98 से।

जे.एस. अत्री अतिरिक्त महाधिवक्ता एवं एल.आर. रथ अपीलकर्ता के लिए।

एस.के. वर्मा (एनपी) प्रतिवादी की ओर से

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया-

न्यायाधिपति अरिजीत पसायत:

इस अपील का तथ्यात्मक मैट्रिक्स दुर्भाग्य से है घृणित और अप्रिय घटनाओं से संबंधित जहां प्रतिवादी (बाद में 'अभियुक्त' के रूप में संदर्भित) जो प्रासंगिक समय पर एक शिक्षक के रूप में काम कर रहा था, उसने अपने छात्रा , एक कम उम्र की लड़की

के साथ शारीरिक ज्ञान प्राप्त करके अपने एनिमेटेड जुनून और यौन सुख को संतुष्ट किया। परिणाम यह हुआ कि शिक्षक और उसके शिष्य का पवित्र रिश्ता कलंकित हो गया। जैसा कि इस न्यायालय ने मदन गोपाल कक्कड़ बनाम नारायण दुबे और अन्य (1992) 2 अपराध 168 में देखा था, ऐसे अपराधी सभ्य समाज के लिए खतरा हैं।

हिमाचल प्रदेश राज्य ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील की है, जिसमें भारतीय दंड संहिता 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी) की धारा 376 और 506 के तहत दंडनीय अपराधों के कथित कमीशन के लिए मुकदमे का सामना करने वाले आरोपियों को बरी करने का निर्देश दिया गया है। विचारण न्यायालय यानी सत्र न्यायालय किन्नौर ने उसे दोषी ठहराया था और 7 साल की कैद और रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। पहले अपराध के लिए 2,000 रुपये और दूसरे अपराध के लिए एक साल और 2,000 रुपये का जुर्माना। इसके अलावा, आरोपी को अभियोजन पक्ष को 10,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया।

यौन हिंसा एक अमानवीय कृत्य होने के अलावा एक महिला की निजता और पवित्रता के अधिकार पर एक गैरकानूनी हस्तक्षेप है। यह उसके सर्वोच्च सम्मान के लिए एक गंभीर झटका है और उसके आत्म-सम्मान और गरिमा को ठेस पहुँचाता है - यह पीड़िता को नीचा दिखाता है और अपमानित करता है और जहाँ पीड़िता एक असहाय मासूम बच्चा या नाबालिग है, तो यह एक दर्दनाक अनुभव छोड़ जाता है। एक बलात्कारी न केवल शारीरिक चोट पहुँचाता है, बल्कि एक महिला की सबसे प्रिय संपत्ति यानी उसकी गरिमा, सम्मान, प्रतिष्ठा और कम से कम उसकी पवित्रता पर भी अमिट दाग छोड़ जाता है। बलात्कार केवल एक महिला के व्यक्तित्व के खिलाफ अपराध नहीं है, यह पूरे समाज के खिलाफ अपराध है। यह, जैसा कि इस न्यायालय ने श्री बोधिसत्व गौतम बनाम मिस सुभ्रा चक्रवर्ती, एआईआर (1996) एससी 922 में कहा है, एक

महिला के संपूर्ण मनोविज्ञान को नष्ट कर देता है और उसे गहरे भावनात्मक संकट में धकेल देता है। यह बुनियादी मानवाधिकारों के खिलाफ एक अपराध है, और पीड़ित के सबसे प्रिय मौलिक अधिकारों, अर्थात्, भारत के संविधान, 1950 (संक्षेप में 'संविधान') के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के अधिकार का भी उल्लंघन है। इसलिए, महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध के मामलों से अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटने की अपेक्षा की जाती है। ऐसे मामलों से सख्ती और सख्ती से निपटने की जरूरत है।' हमारी राय में, एक सामाजिक रूप से संवेदनशील न्यायाधीश महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में जटिल अपवादों और प्रावधानों वाले दंडात्मक प्रावधानों की लंबी धाराओं की तुलना में एक बेहतर वैधानिक कवच है।

हम पीड़िता का नाम बताने का प्रस्ताव नहीं रखते. आईपीसी की धारा 228-ए कुछ अपराधों के पीड़ित की पहचान का खुलासा करना दंडनीय बनाती है। किसी भी मामले का नाम छापना या प्रकाशित करना जिससे किसी भी व्यक्ति की पहचान ज्ञात हो सकती है जिसके खिलाफ धारा 376, 376-ए, 376-बी 376 सी या 376 डी के तहत अपराध हुआ है। आरोप लगाया गया है या अपराध किया हुआ पाया गया तो दंडित किया जा सकता है। यह सच है कि यह प्रतिबंध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के फैसले के मुद्रण या प्रकाशन से संबंधित नहीं है। लेकिन जिस यौन अपराध के लिए धारा 228-ए अधिनियमित किया गया है, उसके पीड़ित के सामाजिक उत्पीड़न या बहिष्कार को रोकने के सामाजिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, यह उचित होगा कि निर्णयों में, चाहे वह इस न्यायालय, उच्च न्यायालय या निचली अदालत के हों। पीड़ित का नाम नहीं दर्शाया जाना चाहिए. हमने फैसले में उसे 'पीड़ित' के रूप में वर्णित करना चुना है। (देखें कर्नाटक राज्य बनाम पुट्टराजा, (2003) 8 सुप्रीम 364)।

मुकदमे के दौरान सामने आया अभियोजन का विवरण मूलतः इस प्रकार है:

28.5.1993 को आरोपी श्री कांत ने पीड़ित को, जो उसकी कक्षा 4 कि छात्रा था, एक प्रश्न हल करने के लिए स्कूल के समय के बाद इंतजार करने के लिए कहा, जबकि उसने अन्य छात्रों को जाने की अनुमति दी। पीड़िता क्लास रूम में ही थी जब आरोपी ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और पीड़िता को फर्श पर लिटा दिया और उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए। वह मना करती रही, रोती रही, चिल्लाती रही, हालांकि, कमरे के दरवाजे बंद थे, इसलिए कोई भी उसकी चीख नहीं सुन सका। फिर उसने उसे धमकी दी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताने की हिम्मत की तो वह उसे नदी में फेंक देगा। धमकी मिलने के कारण उसने यह बात किसी को नहीं बताई।

पहली घटना के कुछ दिनों बाद आरोपी उसे और तीन अन्य छात्रों को अपने कमरे की सफाई के लिए चूहा बाग ले गया था। आरोपी ने बाकी तीन छात्राओं को कमरे से बाहर भेज दिया और उसे कमरे में ही बंद कर दिया. उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और उसे फर्श पर लिटा दिया और उसके साथ फिर से यौन संबंध बनाए।

सितंबर, 1993 में पीड़िता ने स्कूल जाना बंद कर दिया. चूंकि वह नियमित रूप से पेट दर्द की शिकायत करती थी, इसलिए उसकी मां उसे रामपुर अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर (पीडब्लू-1) द्वारा जांच के बाद पीड़िता की मां को पता चला कि वह गर्भवती थी। अपनी मां द्वारा पूछताछ करने पर, पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि उसका गर्भधारण आरोपी द्वारा यौन संबंध बनाने के कारण हुआ था। गांव लौटने के बाद, पीड़िता की मां ने अपने पति से इस मामले पर चर्चा की और फिर ग्राम पंचायत के सदस्य कृष्णा को घटना के बारे में बताया, जिन्होंने मामले की रिपोर्ट पुलिस में करने का सुझाव दिया।

20.11.1993 को पीड़िता ने पुलिस स्टेशन, रामपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई। ऐसी रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर संख्या 365/1993 (एक्स.पीडब्ल्यू3/ए) के तहत धारा 376 और 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था।

जांच के दौरान पीड़िता (पीडब्लू-3) की 20.11.1993 को शाम 4.00 बजे चिकित्सकीय जांच की गई। ऐसी चिकित्सीय जांच रेफ्यूरल अस्पताल, रामपुर के डॉक्टर (पीडब्ल्यू-1) द्वारा की गई थी। उनकी राय में उसकी गर्भधारण अवधि 28 सप्ताह थी।

जांच पूरी होने पर आरोप पत्र पेश किया गया और मामले की सुनवाई शुरू की गई। अभियोजन पक्ष के बयान को आगे बढ़ाने के लिए बारह गवाहों से पूछताछ की गई। मुख्य गवाह स्वयं पीड़िता थीं जिनसे पीडब्लू-3, उसकी माँ (पीडब्लू-4), पिता (पीडब्लू-5) और अन्य गवाहों के रूप में पूछताछ की गई जिन्होंने पीड़िता की उम्र के बारे में बात की थी। पीड़िता के सबूतों पर भरोसा करते हुए विचारण न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया, दोषी ठहराया और उसे उपरोक्त सजा सुनाई।

आरोपी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी दोषसिद्धि और दी गई सजा पर सवाल उठाया। एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय द्वारा ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और बरी करने का निर्देश दिया।

अपीलकर्ता-राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय उचित परिप्रेक्ष्य में तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति का विश्लेषण करने में विफल रहा है और प्रासंगिक मामलों को विचार से बाहर रखा है और अभिमानी निष्कर्ष निकाले हैं और इसलिए, निर्णय को रद्द किया जाना चाहिए। नोटिस तामील होने के बावजूद आरोपी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

जिन कारकों को उच्च न्यायालय ने महत्व दिया है वे हैं (i) पीड़िता की उम्र, जो उच्च न्यायालय के अनुसार 16 वर्ष से अधिक थी (ii) अभियोजन पक्ष द्वारा यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं रखा गया है कि पीड़िता ने सहमति नहीं दी थी अधिनियम के लिए; और (iii) पीड़िता और उसकी मां द्वारा कथित बलात्कार का जो समय बताया गया था, वह चिकित्सीय साक्ष्यों द्वारा असंभाव्य था। इस तथ्य का विशेष संदर्भ दिया गया था कि एक बच्चे का जन्म I0.4.1979 को हुआ था और यदि

कथित बलात्कार पीड़िता और उसकी मां द्वारा बताई गई अवधि के दौरान किया गया है तो वह पूरी तरह से अलग-अलग अवधि होगी। अभियोजन मामले में भेद्यता जोड़ने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी को भी उजागर किया गया था।

हम सबसे पहले उम्र के सवाल से निपटेंगे। रेडियोलॉजिकल परीक्षण से पता चला कि पीड़िता की उम्र 15 से 16 साल के बीच है। यह स्थापित करने के लिए स्कूल रिकॉर्ड प्रस्तुत किए गए कि उसकी जन्मतिथि 1.4.1979 थी। प्रासंगिक दस्तावेज़ एक्स पी डब्लू 6/ए से पी डब्लू 6/सीहैं। उच्च न्यायालय का विचार था कि ये दस्तावेज़ पीड़िता की उम्र स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे क्योंकि एक अन्य दस्तावेज़ एक्सपी डब्लू 7/ए था जो उच्च न्यायालय के अनुसार नहीं था। पीड़ित से संबंधित. केवल इसलिए कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया एक दस्तावेज़, उच्च न्यायालय के अनुसार पीड़ित से संबंधित नहीं था, जो एक्स . पी डब्लू 6/ए से एक्स पी डब्लू 6/सी के साक्ष्य मूल्य को अनदेखा करने के लिए पर्याप्त नहीं था, ये प्रवेश के संबंध में रिकॉर्ड थे। पीड़िता के स्कूल और उसके अध्ययन की अवधि। ये दस्तावेज़ निर्विवाद रूप से साबित करते हैं कि आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि 10.4.1979 थी। इसलिए, घटना की तारीख पर और यहां तक कि जब 20.11.1993 को एफआईआर दर्ज की गई थी तब भी वह लगभग 14 वर्ष की थी। इसलिए, सहमति का प्रश्न वास्तव में कोई मायने नहीं रखता था।

अन्यथा भी ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय गंभीर त्रुटि में पड़ गया है इस निष्कर्ष पर पहुँचना कि पीड़िता ने यह नहीं दर्शाया है कि कार्य उसकी सहमति से नहीं किया गया था। यह दिखाना पीड़िता का काम नहीं था कि कोई सहमति नहीं थी। तथ्यात्मक रूप से भी निष्कर्ष शुरू से ही गलत है, यानी उस चरण से जब एफआईआर दर्ज की गई थी और उसके साक्ष्य में एक स्पष्ट बयान था कि पीड़िता के विरोध के बावजूद बलात्कार जबरन किया गया था। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा पीड़ित पर यह

दिखाने का बोझ डालना गलत था कि कोई सहमति नहीं थी। सहमति का प्रश्न वास्तव में अभियुक्त द्वारा बचाव का मामला है और यह दिखाने के लिए सामग्री रखना उसका काम था कि सहमति थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिरह के दौरान और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए बयान में सहमति की दलील नहीं दी गई थी। वास्तव में संहिता की धारा 313 के तहत बयान में दलील पूरी तरह से इनकार और गलत निहितार्थ थी।

हाईकोर्ट ने पीड़िता और उसकी मां की गवाही पर संदेह करने के लिए तारीखों के संबंध में काल्पनिक गणना करने में भी गलती की है। गवाहों ने जो कहा था वह अनुमानित तारीखें या अवधियाँ थीं, न कि यह कि उन्हें सटीकता के साथ गिना जाना था। जैसा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से पता चलता है, पीड़िता कोई बुद्धिमान लड़की नहीं है। वह तीसरे प्रयास में कक्षा 3 पास कर गई। उसकी माँ, एक देहाती महिला, व्यावहारिक रूप से अनपढ़ है। उनके साक्ष्यों की सूक्ष्म दृष्टि से जांच करना न्यायोन्मुख न्याय व्यवस्था का अपमान होगा। यह जीवन की वास्तविकताओं से बिल्कुल अलग होगा।

उच्च न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने में तथाकथित देरी के लिए अभियोजन पक्ष की बात पर भी अविश्वास किया है। अभियोजन पक्ष ने न केवल कारण बताए हैं, बल्कि देरी क्यों हुई, इस रुख को साबित करने के लिए ठोस सबूत भी पेश किए हैं। विचारण न्यायालय ने वास्तव में स्थिति का विस्तार से विश्लेषण किया और सही निष्कर्ष पर पहुंचा कि एफआईआर दर्ज करने में देरी के कारणों को स्पष्ट रूप से समझाया गया है।

असामान्य परिस्थितियों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी को संतोषजनक ढंग से समझाया। किसी भी स्थिति में, जब बलात्कार के आरोप शामिल होते हैं तो देरी स्वयं आरोपी के लिए कोई राहत देने वाली परिस्थिति नहीं होती है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी को अभियोजन मामले को खारिज करने और इसकी प्रामाणिकता पर संदेह करने के अनुष्ठानिक फार्मूले के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यह अदालत को केवल यह देखने और विचार करने के लिए तैयार करता है कि क्या देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण पेश किया गया है। एक बार जब यह पेश किया जाता है, तो न्यायालय को केवल यह देखना होता है कि यह संतोषजनक है या नहीं। किसी मामले में यदि अभियोजन पक्ष देरी की संतोषजनक व्याख्या करने में विफल रहता है और ऐसी देरी के कारण अभियोजन संस्करण में अलंकरण या अतिशयोक्ति की संभावना है, तो यह एक प्रासंगिक कारक है। दूसरी ओर, विलंब का संतोषजनक स्पष्टीकरण झूठे निहितार्थ या अभियोजन मामले की कमजोरी के अंश को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त है। जैसा कि तथ्यात्मक परिदृश्य से पता चलता है, पीड़िता अपने साथ हुई विपत्ति से पूरी तरह अनजान थी। हालाँकि, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी किसी भी तरह से अभियोजन संस्करण को कमजोर नहीं बनाती है। इन पहलुओं को तुलसीदास कनोलकर बनाम गोवा राज्य, [2003]8 सेकंड 590 में उजागर किया गया था।

उच्च न्यायालय ने काल्पनिक गणनाओं से यह निष्कर्ष निकाला है कि विसंगतियां थीं और केवल अनुमानों और अनुमानों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि एफआईआर दर्ज करने में अस्पष्ट देरी हुई थी। उपरोक्त के मद्देनजर, उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को कायम नहीं रखा जा सकता है। .यह आरोपी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष भी दायर किया गया था, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़ित के साक्ष्य की किसी भी पुष्टि की अनुपस्थिति के संबंध में यह तर्क दिया गया था।

यह अच्छी तरह से स्थापित है कि बलात्कार के अपराध का शिकार होने की शिकायत करने वाली पीड़िता अपराध के बाद सहयोगी नहीं है। कानून का कोई नियम नहीं है कि उसकी गवाही को भौतिक विवरणों की पुष्टि के बिना क्रियान्वित नहीं किया

जा सकता है। वह एक घायल गवाह की तुलना में ऊंचे स्थान पर है। बाद वाले मामले में, शारीरिक चोट लगती है, जबकि पहले मामले में यह शारीरिक होने के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक भी होता है। हालाँकि, अगर अदालत को तथ्यों के आधार पर अभियोजक के बयान को उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार करना मुश्किल लगता है, तो वह प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य की तलाश कर सकती है, जो उसकी गवाही को आश्वासन देगा। आश्वासन, अनुपूरक के संदर्भ में समझी गई पुष्टि की कमी पर्याप्त होगी

पीड़िता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह आरोपी से डरती थी जो उसका शिक्षक था और उसके द्वारा दी गई धमकियों से इस हद तक डरती थी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी से बात की तो उसे शारीरिक नुकसान पहुंचाया जाएगा। आरोपी का यह कहना कि उसे झूठा फंसाया गया क्योंकि पीड़िता का भाई परीक्षा में सफल नहीं हुआ था और इसलिए, उसके परिवार के मन में आरोपी के प्रति द्वेष था, इसे स्वीकार करना मुश्किल है। जिस घटना में आरोपी और पीड़िता की मां और भाई शामिल थे, वह लगभग एक दशक पहले हुई थी। इस बात की दूर-दूर तक संभावना नहीं है कि यह गलत निहितार्थ का आधार होगा। किसी भी हालत में कम उम्र की कोई भी लड़की और उसके माता-पिता किसी व्यक्ति पर जबरन यौन संबंध बनाने का झूठा आरोप लगाकर उसका पूरा भविष्य खतरे में नहीं डालना चाहेंगे।

किसी भी कोण से देखा जाए तो उच्च न्यायालय का निर्णय बचाव योग्य नहीं है और तदनुसार उसे रद्द किया जाता है। विचारण न्यायालय का आदेश बहाल किया जाता है। अभियुक्त को शेष सजा काटने के लिए तुरंत हिरासत में आत्मसमर्पण करना होगा। अपील स्वीकार की जाती है।

बी.बी.बी.

अपील की अनुमति दी जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।